विद्युत् मंत्रालय में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् है :--

| | |
|---|---|
| 1990-91 | 554 |
| 1991-92 | 687 |
| 1992-93 | 772 |
| कुल | 2013 |

(ख) उपरोक्त में से 2008 पत्रों की पावती भेजी गई थी।

(ग) और (घ) 752 पत्रों के उत्तर नकारात्मक और 630 पत्रों के उत्तर सकारात्मक सहित कुल 1650 पत्रों के अंतिम उत्तर भेजे गए थे।

**PROVIDING ASSURED RAlb OF RBOTURN TO FOREIGN INVESTORS**

2663. SHRI ASHOK MITRA : Will the Minister of Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact thai Government propose to provide a 16 per cent assured rate of return in dollar terms to foreign investors in the power scitor.

(b) if so, the procedure of a3<if£ssment of cost and the mechanism of pricing in terms of which such a rate of return is proposed to be ensured; and

(c) the average cost per megawatt tn the foreign investment projects apiffoved so far, and the corresponding cost per megawatt of power projects completed in the country over the past five years ?

THE MINISTEP. OF STATE IN THE MINISTRY OF POVVER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU)) : (a) and (b) The 16 per cent return on equity which will be denominated in dollars in case of foreign equity only would be an elaaent in the fixed cost part of the tariff ftM generating companies.

(c) The average cost per MW involv-ing foreign investment has been established only in so far as the gas based projects are concerned and is estimated at present at Rs- 3.65 crores per MW at 1996 price level. The cost per MW of such prefects cmnpleted during the last 5 years was between Rs. 1 crore per *MW* to Rs. 2.4 crores per MW.

**बिहार में बिजली उत्पादन**

2664. श्री बहुबलेंद्र आनन्द पासवान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दामोदर घाटी निगम" से उत्पन्न बिजली को बिहार के बाहर से जाया जा रहा है;

(ख) क्या सुमरी तलैया, कोपाकं, सामधाग और पोत बांधों से उत्पन्न बिजली को भी बिहार से बाहर ले जाया जा रहा है;

(ग) क्या बिहार का कोयला, ताम्बा, अभ्रक, एल्यूमिनियम, जस्ता का भरपूर दोहन करने के लिए तमाम विद्युत चालित रेलें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की शान बढ़ा रही हैं जबकि पूरा बिहार बिजली के बिना अंधकार में डूबा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार को आवश्यक मात्रा में बिजली प्रदान करने का विचार रखती है ताकि वहां उद्योगों को बढ़ावा मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक दिन कितनी बिजली दिए जाने की सम्भावना है और कब तक ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडु) : (क) से (ङ) दामोदर घाटी निगम प्रणाली में उत्पादित विद्युत को बिहार व पश्चिम बंगाल राज्य और बड़े उपभोक्ताओं जैसे रेलवे, स्टील, कोयला आदि को एक निर्धारित फार्मूला के अनुसार आवंटित किया जाता है। बिहार अपने बकाया हिस्से की दामोदर घाटी निगम प्रणाली और दूसरे केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन, केन्द्रों दोनों से प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। केन्द्रीय विद्युत् उत्पादक एजेंसियां, राज्य बिजली बोर्डों को बड़ी मात्रा में विद्युत् की आपूर्ति करते हैं और अनेक उपभोक्ताओं जैसे उद्योगों को विद्युत् का वितरण करना, राज्य बिजली बोर्डों की जिम्मेवारी है। बिहार राज्य में विद्युत् की अपर्याप्त आपूर्ति के लिए, बिहार राज्य का विद्युत् संयंत्र का घटिया कार्य निष्पादन मुख्य रूप से उत्तर दायी रहा है। वर्ष 1992-93 के